पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 की द्वितीय अपील संख्या 502

==========

1. प्रधान सचिव सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. मुख्य अभियंता, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. अधीक्षण अभियंता सड़क निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर
4. कार्यकारी अभियंता सड़क निर्माण विभाग, मुज़फ़्फ़रपुर

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. पूनम कुमारी शर्मा पति: स्वर्गीय नागेश्वर ठाकुर निवासी: गाँव- बलुआ, पोस्ट ऑफिस- डुमरा, थाना- रुन्नीसैदपुर, जिला- सीतामढ़ी, वर्तमान पता सी/ओ राधेश्याम ठाकुर, मोहल्ला- साहू रोड, दीपक सिनेमा के पास, जिला- मुजफ्फरपुर
2. बिहार राज्य, जिला कलेक्टर, मुज़फ़्फ़रपुर के माध्यम से
3. अंचल अधिकारी, कांति, मुजफ्फरपुर

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री पी. के. शाही, महाधिवक्ता
श्री एस. डी. यादव, ए. ए. जी-9
श्री दिनेश महाराज, ए. ए. जी.-11 के ए. सी.
श्री जितेंद्र कुमार, पूर्व ए. ए. जी.-11 के ए. सी.

उत्तरदाता संख्या 1 के लिएः श्री आदित्य शंकर प्रसाद, अधिवक्ता
श्री संचे श्रीवास्तव, अधिवक्ता
श्री सुशांत श्रीवास्तव, अधिवक्ता

श्री आशीष कुमार पालित, अधिवक्ता

हस्तक्षेपकर्ता के लिएः श्री उपेंद्र कुमार चौबे, अधिवक्ता।

==========

परिसीमा अधिनियम---धारा 5----सिविल प्रक्रिया संहिता---द्वितीय अपील----आवश्यक पक्ष---अपील दायर करने में देरी के लिए "पर्याप्त कारण"---द्वितीय अपील का ज्ञापन दायर करने में 5 वर्ष और 6 महीने की देरी को माफ करने के लिए आवेदन---अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क कि जबकि वे विषय-वस्तु में आवश्यक पक्ष थे, उन्हें अंतर्निहित शीर्षक मुकदमे में पक्ष नहीं बनाया गया था और इस तरह वे ऐसी किसी भी कार्यवाही के संबंध में अनभिज्ञ थे और अचानक जब निष्पादन न्यायालय के अधिकारी अंतर्निहित शीर्षक मुकदमे में पारित डिक्री के निष्पादन के लिए आए तो उन्हें इसके बारे में पता चला।

निष्कर्ष: विलम्ब को क्षमा करने के लिए, न्यायालय पर विवेकाधिकार की जानबूझकर पुष्टि की गई है ताकि उस संबंध में न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके---सीमा अधिनियम की धारा 5 में "पर्याप्त कारण" शब्द को एक उदार अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके, जब विलम्ब किसी जानबूझकर की गई रणनीति, सद्भाव की कमी, कार्रवाई में जानबूझकर या अपीलकर्ताओं की ओर से लापरवाही के कारण न हो---अपीलकर्ताओं के पास वाद की संपत्ति का कब्जा है और उनका हित इसमें शामिल है और वादी ने अपीलकर्ताओं को वाद या अपील में पक्षकार बनाने का विकल्प नहीं चुना है---रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सामग्री नहीं है जो यह सुझाव दे कि अपीलकर्ताओं को वाद या अपील के बारे में जानकारी थी---अपीलकर्ताओं ने विलम्ब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण दिए हैं---अपील ज्ञापन दाखिल करने में विलम्ब को क्षमा किया गया---आवेदन स्वीकृत किया गया। **(पैरा-1, 4, 13, 14)**

1998(7) एससीसी 123 .....**पर भरोसा किया गया।**

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री खातिम रेज़ा

सीएभी आदेश

26 20-01-2025 ***पुनः आई.ए. संख्या 46/2019***

यह अंतर्वर्ती आवेदन अपील ज्ञापन दाखिल करने में 5 साल और 6 महीने की देरी को माफ करने के लिए दायर किया गया है।

2. यह द्वितीय अपील एड हॉक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-V, मुजफ्फरपुर द्वारा शीर्षक अपील संख्या 23/2012 में पारित दिनांक 09.02.2012 और 16.04.2013 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध दायर की गई है जिसके द्वारा 2008 के शीर्षक मुक़दमा संख्या 632 में उप न्यायाधीश-4, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 और 2/ उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के खिलाफ पुष्टि की गई है। साथ ही विवादित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाली याचिका भी दायर की गई है। हालाँकि, अपीलकर्ता मुकदमे में पक्षकार नहीं थे।दूसरी अपील दायर करने की अनुमति मांगने के लिए उक्त आवेदन को दिनांक 11.05.2023 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई है।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री पी.के. शाही और उनकी सहायता के लिए विद्वान एएजी-9 श्री एस.डी. यादव और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आदित्य शंकर प्रसाद को सुना गया।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त मुकदमा बिहार राज्य के खिलाफ जिला कलेक्टर, मुजफ्फरपुर और सर्कल अधिकारी, कांति, मुजफ्फरपुर के माध्यम से दायर किया गया था, जबकि प्रश्नगत संपत्ति अपीलार्थियों (सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार) की है और उन्हें मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था और वे विषय वस्तु में आवश्यक पक्षकार थे और उनके अधिकार प्रति-न्यायिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने विवादित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध यह अपील दायर की यह

प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ऐसी किसी भी कार्यवाही के संबंध में अनजान थे और अचानक निष्पादन न्यायालय के अधिकारी शीर्षक मुकदमा संख्या 632/2008 में पारित डिक्री के निष्पादन के लिए आए और फिर उन्हें इसके बारे में पता चला। बिहार राज्य के विरुद्ध विवादित निर्णय और डिक्री के निष्पादन के लिए डिक्री धारक द्वारा निष्पादन वाद संख्या 05/2014 जिला कलेक्टर, मुजफ्फरपुर, अंचल अधिकारी, कांटी और कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, सड़क निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर के माध्यम से दायर किया गया है, हालांकि कार्यपालक अभियंता यांत्रिक प्रमंडल सड़क निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर वाद या अपील में पक्ष नहीं थे। निष्पादन वाद की स्वीकृति के पश्चात अपीलकर्ता संख्या सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए। विद्वत निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 तथा अपीलकर्ता संख्या 4 के खिलाफ नोटिस के 30 दिनों के पारित होने के बाद नोटिस की सेवाओं को स्वीकार कर लिया। यह आगे तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त निष्पादन याचिका के कॉलम-10 से यह स्पष्ट है कि कार्यकारी अभियंता, यांत्रिक प्रभाग, सड़क निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर और जिला कलेक्टर, मुजफ्फरपुर के खिलाफ डिक्री के निष्पादन की मांग की गई है।

5. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि कार्यालय-प्रभारी/नजीर, सिविल कोर्ट मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा दिनांक 14.06.2018 को नोटिस जारी किया गया था।उक्त नोटिस कार्यकारी अभियंता मैकेनिकल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में पत्र संख्या 373 दिनांक 14/15.06.2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसमें भूमि को खाली करने का निर्देश जारी किया गया था, क्योंकि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थियों की है और इसलिए, उपरोक्त पत्र कार्यकारी अभियंता, मैकेनिकल द्वारा अपने पत्र संख्या 150 दिनांक 17.09.2018 के माध्यम से अग्रेषित किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों को पहली बार विवादित निर्णय और डिक्री के बारे में पता चला, उसके बाद, अपीलार्थी नं 4 ने अधिवक्ता से परामर्श किया, जिन्होंने अपील के आधार तैयार किए और इसके अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। अपील के आधारों को मंजूरी दे दी गई और अपीलार्थी सं. 4 तत्काल मामले में दूसरी अपील

दायर करके विवादित निर्णयों और डिक्री पर हमला करने के लिए प्राधिकरण के साथ।इसके तुरंत बाद 27.11.2018 पर अपील का ज्ञापन दायर किया गया है।अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने डिक्री के निष्पादन के संबंध में गंभीर आपत्ति जताई।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमे में पारित डिक्री निष्पादन योग्य नहीं है क्योंकि वाद की संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व और ब्याज की घोषणा और कब्जे की पुष्टि के लिए राहत मांगी गई और यह भी घोषित करने के लिए कि वाद की संपत्ति सर्वेक्षण प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षण सर्वेक्षण खाते में बिहार राज्य के नाम पर गलत और अवैध रूप से दर्ज किया गया।राहत से यह स्पष्ट है कि कब्जे की वसूली के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील संख्या 1 ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को 09.02.2012 दिनांकित निर्णय और डिक्री के पारित होने की जानकारी थी। उपरोक्त मुकदमा बिहार राज्य के खिलाफ दायर किया गया था और वर्तमान अपीलार्थी सं 1 बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर बिहार राज्य की एक साधन के अलावा और कुछ नहीं है। सड़क निर्माण विभाग बिहार सरकार का विभाग है जो सड़कों के निर्माण और अन्य कार्यों को देखता है, जबकि जिले का कलेक्टर राज्य सरकार के तहत सभी विभागों का प्रभारी होता है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 और (बिहार राज्य) मुकदमे में एक पक्षकार था और अपील में भी जो कि कलेक्टर, मुजफ्फरपुर और सर्कल अधिकारी, कांति के माध्यम से दायर की गई थी और यह अपीलार्थियों की जानकारी में अच्छी तरह से था।

7. वर्तमान अपील 90 दिनों की निर्धारित अवधि से बहुत आगे दायर की गई है और लगभग 5 साल 6 महीने से अधिक की अत्यधिक देरी हुई है। अपीलार्थियों के पास देरी की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। **मज्जी सन्नेम्मा @ सन्यासीराव बनाम रेड्डी श्रीदेवी और अन्य** के मामले **2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1260** में रिपोर्ट मामले पर भरोसा किया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "*भले ही सीमा किसी पक्ष के*

अधिकारों को कठोर रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसे कानून द्वारा निर्धारित होने पर अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए जब।" **अजय डबरा बनाम प्यारे राम** ने **2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 92** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है जिसमें यह माना गया है

"13. बासवराज बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी [(2013) 14 एस. सी. सी. 81] के मामले में इस न्यायालय ने पर्याप्त कारण की कमी के कारण देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन को खारिज करते हुए पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला हैः

> *"15. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला अदालत में सीमा से परे प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह समझाना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त कारण जिसने उसे उसे सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोका ।यदि कोई पक्ष लापरवाही करता हुआ पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी ओर से ईमानदारी की कमी पाई जाती है, या लगन से कार्य नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, तो देरी को माफ करने के लिए कोई उचित आधार नहीं हो सकता है।किसी भी अदालत को किसी भी शर्त को लागू करके इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ करने में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।आवेदन पर निर्णय केवल विलंब की माफी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर किया जाना है।यदि किसी वादी को बिना किसी औचित्य के समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त रखना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक आदेश पारित करने के बराबर है और यह विधायिका की घोर अवहेलना करने के समान है।"*

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि देरी को माफ करने के विवेकाधिकार का उपयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और यदि लापरवाही, निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी के लिए पक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति की उदारता से व्याख्या नहीं की जा सकती है।

8. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि देरी को उदारता के मामले के रूप में माफ नहीं किया जा सकता है और पर्याप्त न्याय प्रदान करना दूसरे पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए नहीं है।वर्तमान मामले में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है।देरी को केवल इसलिए माफ किया जा सकता है क्योंकि कुछ व्यक्तियों को उनके अपने मामले के तथ्यों पर राहत दी गई है।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह परीक्षण करने के लिए कानून निर्धारित किया है कि प्रस्तावित अपील दायर करने में अत्यधिक देरी को माफ किया जाना चाहिए या नहीं। इस मामले का आधार प**थपति सुब्बा रेड्डी (मृत्यु) एल.आर.एस. एवं अन्य बनाम विशेष उप समाहर्ता (एलए)** द्वारा 08.04.2024 को तय किया गया, जिसमें पैराग्राफ संख्या 26 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के प्रावधान और विधि पर सामंजस्यपूर्ण विचार से यह स्पष्ट है किः

(i) सीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है कि मुकदमेबाजी का अंत स्वयं के अधिकार के बजाय उपचार के अधिकार को जब्त करके किया जाना चाहिए;

(ii) एक अधिकार या उपाय जिसका लंबे समय से उपयोग या लाभ नहीं उठाया गया है, वह एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाना चाहिए या अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए;

(iii) सीमा अधिनियम के प्रावधानों को अलग तरह से समझा जाना चाहिए, जैसे कि धारा 3 को सख्त अर्थों में समझा जाना चाहिए जबकि धारा 5 को उदारता से समझा जाना चाहिए;

(iv) पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए, यद्यपि उदार दृष्टिकोण, न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण या पर्याप्त न्याय के कारण को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग सीमा अधिनियम की धारा 3 में निहित सीमा के पर्याप्त कानून को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है;

(v) न्यायालयों को देरी को माफ करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है यदि पर्याप्त कारण समझाया गया था, लेकिन शक्ति का प्रयोग प्रकृति में विवेकाधीन है और इसका उपयोग तब भी नहीं किया जा सकता है जब विभिन्न कारकों के लिए पर्याप्त कारण स्थापित किया जाता है जैसे कि, जहां अत्यधिक देरी, लापरवाही और उचित तत्परता की कमी है;

(vi) केवल कुछ व्यक्तियों को इसी तरह के मामले में राहत मिली है, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य भी उसी लाभ के हकदार हैं यदि अदालत अपील दायर करने में देरी के लिए दिखाए गए कारण से संतुष्ट नहीं है;

(vii) देरी को माफ करने में मामले के गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है; और;

(viii) विलम्ब क्षमा आवेदन पर विलम्ब को माफ करने के लिए निर्धारित मापदंडों पर निर्णय लिया जाना चाहिए इस कारण देरी को अनदेखा करना कि शर्तें लगाई गई हैं, वैधानिक प्रावधान की अवहेलना के समान है।"

10. वादी/प्रत्यर्थी के वकील का निवेदन है कि यदि लापरवाही के लिए अपीलार्थियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो आवश्यक रूप से देरी को माफ नहीं किया जाएगा।

"इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा विवेक के सही प्रयोग के लिए वास्तविक परीक्षा समय का भौतिक संचालन नहीं है, बल्कि परीक्षण यह है कि क्या देरी के कारण, अपीलार्थी की ओर से ऐसी लापरवाही है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि अपना दावा छोड़ दिया है या जहां अपीलकर्ताओं ने रिट अदालत का रुख किया है, वहां तीसरे पक्ष के अधिकार अस्तित्व में आ गए हैं जिन्हें तब तक बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उचित देरी के लिए स्पष्टीकरण न हो।" यह दृष्टिकोण **नगर परिषद अहमद नगर और ए.एन.आर. बनाम शाह हैदर 2000 (2) एस. सी. सी. 48** में सूचित मामले में लिया गया है।

11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब बिहार राज्य स्वयं एक कार्यवाही में एक पक्ष था और वह योग्यता के आधार पर मामले को खो देता है और यह स्थापित हो गया कि बिहार राज्य को कोई चिंता नहीं है जब प्रश्नगत भूमि के साथ-साथ बिहार राज्य के नाम पर पुनरीक्षण सर्वेक्षण खतियान में प्रविष्टि एक गलत प्रविष्टि थी तो बिहार राज्य के एक विभाग के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने का अवसर कैसे उत्पन्न होता है।अपीलार्थी उक्त अत्यधिक विलम्ब के कारण को पर्याप्त रूप से समझाने में बुरी तरह विफल रहा है, इसलिए वर्तमान अपील में विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता है।

12. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों के साथ-साथ बार में उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सावधानीपूर्वक और चिंतित विचार करने पर विचार करते हुए, वाद और उसके निर्णय के संबंध में अपीलार्थियों के ज्ञान पर विचार करना आवश्यक है।

13. यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि अपीलकर्ता को न तो मुकदमे में और न ही अपील में पक्ष बनाया गया था। अनुसूची-1 भूमि पर वादी के अधिकार, स्वामित्व और हित की घोषणा और अनुसूची-1 भूमि पर कब्जे की पुष्टि के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया गया था और यह भी घोषणा की गई थी कि बिहार राज्य का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है और इस तरह से पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि गलत है।यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमा वादी/प्रतिवादी नं. 1 जिला कलेक्टर, मुजफ्फरपुर और सर्कल अधिकारी, कांति, मुजफ्फरपुर के

माध्यम से बिहार राज्य के खिलाफ।मुकदमा तय किया गया था।उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, बिहार राज्य ने जिला कलेक्टर और सर्कल अधिकारी, कांति के माध्यम से शीर्षक अपील संख्या 23/2012 दायर की।अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी/प्रत्यर्थी ने शिकायत की राहत संख्या (i) में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया "अदालत की प्रक्रिया द्वारा कब्जा देने के रूप में या वैकल्पिक रूप से" जिसे निचली अपीलीय अदालत ने 27.02.2013 पर अनुमति दी थी और तदनुसार वाद में संशोधन किया गया था।इसके बाद, वादी ने न केवल प्रतिवादी 1 और 2 के खिलाफ, उप न्यायाधीश-IV, मुजफ्फरपुर के समक्ष 2014 का शीर्षक निष्पादन मामला संख्या 05 वाला निष्पादन मामला दायर किया बल्कि कार्यकारी अभियंता, यांत्रिक प्रभाग, सड़क निर्माण विभाग (अपीलार्थी सं4) के खिलाफ भी.बाद में, इसे उप न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिम, मुजफ्फरपुर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। वादी/प्रत्यर्थी के मामले के अनुसार, कब्जे का वितरण 18.11.2018 पर किया गया था और नजीर के कब्जे की रिपोर्ट का वितरण विद्वान उप न्यायाधीश-II, पश्चिम, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा 24.11.2018 पर किया गया था।बाद में, कब्जे की डिलीवरी की पुष्टि दिनांक 03.10.2019 के आदेश द्वारा की गई थी।हालाँकि, अपीलकर्ताओं को कार्यालय-प्रभारी, नजीर, सिविल कोर्ट, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा कार्यकारी अभियंता यांत्रिक प्रभाग के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 373 दिनांक 14/15.06.2018 के माध्यम से जारी किया गया नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें वस्तुओं की सूची तैयार करने के बाद 29.06.2018 तक प्रश्नगत भूमि को खाली करने का अनुरोध किया गया था ताकि वाद भूमि के कब्जे की डिलीवरी वादी डिक्री धारक को सौंपी जा सके।डिक्री धारक-प्रतिवादी के मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर सड़क निर्माण विभाग का कब्जा है।सड़क संविधान विभाग को मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया है।2014 के निष्पादन मामला संख्या 05 के आदेश पत्र के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी 1 और 2 और अपीलार्थी सं 4 के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही में जारी किए गए नोटिस को 30 दिनों के अंतराल के बाद दिनांक 06.11.2015 के आदेश के अनुसार वैध रूप में भी माना गया था ।

शीर्षक निष्पादन प्रकरण संख्या 05/2014 के आदेश पत्र से भी यह स्पष्ट है कि उपरोक्त निष्पादन कार्यवाही में जारी नोटिस के संबंध में कोई तामील रिपोर्ट नहीं है। यह अपीलार्थियों का मामला है कि उन्हें कार्यालय-प्रभारी, नजीर द्वारा पत्र संख्या 373 दिनांक 04/2018/06/2018 और पत्र संख्या 150 दिनांक 17.09.2018 के माध्यम से जारी किए गए नोटिस प्राप्त हुए, फिर उन्हें विवादित निर्णय और डिक्री के बारे में पता चला।इसके बाद, अपीलार्थियों के जोड़ीदार ने निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए अनुरोध दायर किया जो प्राप्त किया गया था और अपीलार्थी नं। 4 ने अधिवक्ता के साथ परामर्श किया और संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी मंजूरी के बाद सीमा याचिका के साथ 27.11.2018 पर अपील का वर्तमान ज्ञापन दायर किया।

14. पक्षकारों द्वारा किए गए उपरोक्त तथ्यों और प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, विलंब को माफ करने के लिए, अदालत में विवेक की जानबूझकर पुष्टि की गई है ताकि न्यायिक शक्ति और विवेक का उपयोग पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके। सीमा अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण को समझा जाना चाहिए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मामले की प्रकृति के आधार पर उचित, व्यावहारिक, व्यावहारिक और उदार तरीके से लागू किया जाना चाहिए।सीमा अधिनियम की धारा 5 में "पर्याप्त कारण" शब्द को एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके, जब देरी किसी भी जानबूझकर रणनीति सद्भावना की कमी, जानबूझकर की गई कार्रवाई अथवा अपीलकर्ताओं की ओर से लापरवाही के कारण न हो।

15. मुकदमे में की गई प्रार्थना को देखते हुए, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की पुष्टि मूल रूप से मांगी गई थी।बाद में, 2013 में अपीलीय चरण में, अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से कब्जे की वसूली के लिए वैकल्पिक अनुरोध किया गया था जिसे अपीलीय अदालत ने अनुमति दी थी।यहां तक कि वादी/प्रत्यर्थी ने भी प्रश्नगत भूमि पर कब्जा करने वाले के खिलाफ प्रार्थना नहीं की, अर्थात अपीलकर्ता सं 4. अपीलार्थियों के पास वाद संपत्ति है और उनका हित शामिल है और वादी ने अपीलार्थियों को वाद या अपील में पक्षकार

बनाने का विकल्प नहीं चुना है।अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह सुझाव दे कि अपीलार्थियों को मुकदमे या अपील के बारे में जानकारी थी।

16. उपरोक्त तथ्यों और किए गए कथनों में, अपीलकर्ताओं ने देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिए हैं। **बालकृष्णन बनाम एम. के कृष्णमूर्ति** ने **1998 (7) एस.सी.सी. 123** मामले में निर्धारित उक्ति के अनुसार यह माना गया है कि :

> "*यह स्वयंसिद्ध है कि विलंब की क्षमा अदालत के विवेकाधिकार का विषय है सीमा अधिनियम की धारा 5 में यह नहीं कहा गया है कि इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब विलंब एक निश्चित सीमा के भीतर हो।देरी की अवधि कोई बात नहीं है, स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही एकमात्र मानदंड है ।कभी-कभी स्वीकार्य स्पष्टीकरण की कमी के कारण सबसे छोटी सीमा की देरी अक्षम्य हो सकती है, जबकि कुछ अन्य मामलों में बहुत लंबी सीमा की देरी को माफ किया जा सकता है क्योंकि इसका स्पष्टीकरण संतोषजनक है।एक बार जब अदालत स्पष्टीकरण को पर्याप्त के रूप में स्वीकार कर लेती है तो यह विवेकाधिकार के सकारात्मक प्रयोग का परिणाम होता है और आम तौर पर उच्च न्यायालय को इस तरह के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए, बहुत कम प्रत्यावर्ती अधिकार क्षेत्र में, जब तक कि विवेकाधिकार का प्रयोग पूरी तरह से असमर्थनीय आधारों या मनमाना या विकृत न हो।लेकिन यह एक अलग मामला है जब पहली अदालत देरी को माफ करने से इनकार कर देती है।ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय देरी के लिए दिखाए गए कारण पर नए सिरे से विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा और यह ऐसे उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि वह निचली अदालत के निष्कर्ष तक भी अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आए।*"

17. उपरोक्त उक्ति में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि एक बार जब कोई अदालत स्पष्टीकरण को पर्याप्त मान लेती है, तो यह विवेक के सकारात्मक प्रयोग का परिणाम है।

18. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, अपील का ज्ञापन दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया जाता है।

19. तदनुसार, आई.ए. संख्या 46/2019 की अनुमति है।

(खातिम रेज़ा, न्यायमूर्ति)

प्रभात/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।